सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं-जगत प्रवाह परिवार

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 37 प्रति सोमवार, 26 जनवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या गौ मांस के पैसों से अपनी राजनीति चमका रही हैं भोपाल महापौर मालती राय और उनके राजनीतिक आका?

आस्था, कानून और जवाबदेही के चौराहे पर खड़े मंत्री विश्वास सारंग

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

भोपाल में अभी हाल में हुई एक शर्मनाक घटना ने भाजपा के धार्मिक नैरेटिव वाली राजनीति को बदल कर रख दिया है। दरअसल भोपाल की महापौर मालती राय ने अक्टूबर 2025 में असलम चमड़े नाम के कसाई की कंपनी को सारे नियम ताक पर रखवाकर अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की चाबी दे दी। गौर करने वाली बात यह है कि मालती राय की पूरी राजनीति उनके राजनीतिक आका मंत्री विश्वास सारंग के आसपास घूमती है। पावर गैलेरी में तो सारंग को शैडो मेयर भी कहा जाता है, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या गौ मांस के पैसो से ही नरेला विधानसभा में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जहां मोदी-शाह समेत पूरी बीजेपी देश में "जी राम जी" को लेकर मुद्दा बना रही है ठीक उसी समय भोपाल राजधानी में एक गौ तस्कर ने भोपाल महापौर में संरक्षण में 250 गायें कटवा दी। यह मामला तो पकड़ में आ गया पता नहीं कितनी हजारों गायों का वध अभी तक इन लोगों ने करवा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि विश्वास सारंग और उनके खास लोगों के नाम भोपाल के असामाजिक तत्व चाहे सट्टा किंग मस्तान, क्रिमिनल जुबेर, ड्रग्स एवं क्रिमिनल मछली परिवार या गौ तस्कर असलम चमड़ा के साथ क्यों जुड़ते हैं और वो उनके रहनुमा निकलते हैं। सबसे बेशर्मी की बात है कि बीजेपी जो इन सब मुद्दे पर राजनीति करती है वो अपने मंत्री विश्वास सारंग और मालती राय के कुकर्मों पर चुप क्यों है। आधुनिक स्लॉटर हाउस में कथित रूप से प्रतिबंधित पशुओं के मांस कटने के मामले ने सत्ता, संगठन और प्रशासन तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क से लेकर मंत्रालय और नगर निगम परिषद के दफ्तरों तक अफरा-तफरी का माहौल है।

गौ-हत्या आस्था, कानून और संवेदनशीलता का सवाल

स्लॉटर हाउस से जुड़ा कथित गौ-हत्या का मामला केवल एक प्रशासनिक या कानूनी विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक संवेदनाओं से सीधे तौर पर जुड़ गया है। गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है और मध्यप्रदेश में गौ-संरक्षण से जुड़े कानून भी बेहद सख्त हैं। ऐसे में स्लॉटर हाउस परिसर में प्रतिबंधित पशु के मांस से जुड़े आरोपों ने जनभावनाओं को आहत किया है। (शेष पेज 3 पर)

स्वाभिमान, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रतीक है कमलनाथ का 15 माह का कार्यकाल

कांग्रेस नेताओं की चाणक्य नीति से हुआ था कमलनाथ सरकार का पतन

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति हमेशा ही उतार-चढ़ाव और रणनीति का जीवंत उदाहरण रही है। यहाँ पर सत्ता की राजनीति में न केवल शक्ति संघर्ष होता है, बल्कि नेताओं की दूरदर्शिता, रणनीतिक सोच और व्यक्तिगत स्वाभिमान भी परखा जाता है। ऐसे ही एक दृष्टांत के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल और नेतृत्व ने यह साबित किया कि राजनीति में केवल सत्ता का अधिकार ही नहीं, बल्कि मूल्य, स्वाभिमान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना और उनके द्वारा सरकार का संचालन करना एक ऐसे दौर में हुआ जब प्रदेश में जनता की अपेक्षाएं और राजनीतिक परिस्थितियाँ अत्यंत चुनौतीपूर्ण थीं। कमलनाथ ने पार्टी के हित और जनता की सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनके कार्यकाल के 15 महीनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेता केवल पद और सत्ता की लालसा में नहीं, बल्कि जनता की भलाई और न्यायप्रिय प्रशासन में भी निष्ठावान हो सकता है। (शेष पेज 6 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गांव-गांव तक पहुंची प्रगति की राह, पीएमजीएसवाई से बदला विकास का भूगोल

-विजया पाठक

पहाड़ों, घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक संपर्कहीनता की समस्या से जूझता रहा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला आज विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। जिन गांवों तक कभी मौसम के भरोसे पहुंचा जा सकता था, जहां बरसात में सड़कें कट जाती थीं और लोग महीनों तक अलग-थलग पड़ जाते थे, वहां आज पक्की सड़कों से विकास की रफ्तार दौड़ रही है। यह परिवर्तन संभव हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रभावी क्रियान्वयन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास की असली कसौटी शहरों की चमक नहीं, बल्कि गांवों की मजबूती है। इसी सोच के साथ पीएमजीएसवाई को केवल एक निर्माण योजना न मानकर ग्रामीण जीवन को बदलने का सशक्त माध्यम बनाया गया। एमसीबी जिले में आज सड़कों का जो जाल बिछा है, वह केवल कंक्रीट और डामर का ढांचा नहीं, बल्कि गांवों की नई किस्मत, ग्रामीण जीवन की धड़कन और समग्र विकास की मजबूत नींव है।

ग्रामीण जीवन की धड़कन बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पिछले कुछ वर्षों में पीएमजीएसवाई ने एमसीबी जिले के विकास के भूगोल को पूरी तरह बदल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले के अधिकांश गांव अब पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। जहां अभी कार्य शेष है, वहां निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी गई, ताकि कोई भी गांव मुख्यधारा से पीछे न छूटे। सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि अंतिम छोर पर बसे गांव तक भी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचें। इसी नीति का परिणाम है कि आज एमसीबी जिले में सड़कें ग्रामीण विकास का आधार बनकर उभरी हैं। इन सड़कों ने न केवल आवागमन को सुगम बनाया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और रोजगार के नए द्वार खोले हैं। (शेष पेज 3 पर)

सम्पादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की जिद का विश्व पर असर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को "खरीदने" की इच्छा व्यक्त करना पहली नजर में भले ही एक अजीब या अव्यावहारिक विचार लगे, लेकिन इसके निहितार्थ वैश्विक राजनीति, भू-रणनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए अत्यंत गंभीर रहे हैं। ट्रंप की यह जिद केवल एक भूभाग को हासिल करने की आकांक्षा नहीं थी, बल्कि यह 21वीं सदी की महाशक्ति राजनीति में उभरते नए संघर्षों और प्राथमिकताओं का प्रतीक बन गई।ग्रीनलैंड, जो भौगोलिक रूप से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। रणनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र आर्कटिक महासागर में स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है, वहां नए समुद्री मार्ग, खनिज संसाधन और ऊर्जा संभावनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ में हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की जिद इसी व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा थी।

ट्रंप के इस बयान ने सबसे पहले अमेरिका और डेनमार्क के संबंधों में असहजता पैदा की। डेनमार्क ने इसे सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड "बिकाऊ नहीं" है। इससे यह सवाल उठा कि क्या आधुनिक विश्व में संप्रभुता को अब भी सौदेबाजी की वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। ट्रंप का यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाता है, जहां शक्तिशाली देश छोटे या रणनीतिक क्षेत्रों को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर भी प्रश्नचिह्न लगा। वैश्विक स्तर पर इस जिद का एक बड़ा प्रभाव यह रहा कि आर्कटिक क्षेत्र अचानक विश्व राजनीति के केंद्र में आ गया। रूस पहले से ही आर्कटिक में सैन्य और आर्थिक गतिविधियां बढ़ा रहा है, जबकि चीन स्वयं को "नियर-आर्कटिक स्टेट" बताकर वहां निवेश और शोध के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ट्रंप के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका भी इस क्षेत्र को भविष्य की शक्ति-संतुलन की कुंजी मानता है। इससे आर्कटिक के सैन्यीकरण और प्रतिस्पर्धा की आशंका और बढ़ गई।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोटे और स्वायत्त क्षेत्रों पर भी पड़ा। ग्रीनलैंड की स्थानीय आबादी ने यह महसूस किया कि वैश्विक शक्तियां उनके भूभाग को रणनीतिक मोहरे के रूप में देख रही हैं, न कि वहां रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं और अधिकारों के संदर्भ में। इससे आत्मनिर्णय के अधिकार और स्थानीय स्वायत्तता की बहस को नई धार मिली। ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की जिद ने अमेरिकी विदेश नीति की शैली पर भी सवाल खड़े किए। पारंपरिक कूटनीति, सहयोग और बहुपक्षीय संवाद के बजाय, यह रवैया शक्ति प्रदर्शन और सौदेबाजी पर आधारित दिखाई दिया। इससे अमेरिका की वैश्विक छवि को भी आघात पहुंचा और सहयोगी देशों के बीच यह संदेश गया कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जिद एक व्यक्ति की सनक भर नहीं थी, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति का संकेतक थी। इसने आर्कटिक क्षेत्र को नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना दिया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अविश्वास को बढ़ाया और संप्रभुता तथा आत्मनिर्णय जैसे मूल सिद्धांतों पर बहस छेड़ दी। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि दुनिया इस तरह की शक्ति-केंद्रित राजनीति को स्वीकार करती है या सहयोग और संतुलन की राह चुनती है।

सियासी गहमागहमी

हिरासत में कुरैशी, कई नेताओं की सांसे फूल रही

एसआईटी की हिरासत में असलम कुरैशी क्या पहुँचे, राजनीति के वातानुकूलित कमरों में अचानक ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। जिन नेताओं की सांसें आम दिनों में मीडिया कैमरों के सामने बड़े आराम से चलती थीं, वे अब गहरी-गहरी सांसें लेते नजर आ रहे हैं मानो योग शिविर अचानक अनिवार्य हो गया हो। असलम कुरैशी की हिरासत ने यह साबित कर दिया कि फाइलें बोलती नहीं, पर खुलती जरूर हैं। और जब खुलती हैं, तो कई नामों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ नेताओं को अचानक अपने पुराने फोन याद आने लगे हैं, तो कुछ को अपने ड्राइवर, पीए और "दोस्त" बहुत संदिग्ध लगने लगे हैं। कोई कह रहा है, "मुझे कुछ याद नहीं," तो कोई अचानक आध्यात्मिक हो गया है जप, तप और मौन व्रत का सहारा। जो नेता कल तक जांच एजेंसियों को "राजनीतिक हथियार" बता रहे थे, आज वही "निष्पक्ष जांच" की माला जपते दिख रहे हैं बस शर्त इतनी कि जांच "दूसरी दिशा" में चली जाए। बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे एसआईटी नहीं, मौसम विभाग हो कब बारिश होगी, किस पर होगी, कोई नहीं जानता।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

राजनीति में "पूर्व" शब्द जितना साधारण लगता है, उतना ही भारी भी होता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मामले में भी यही दिख रहा है। सत्ता जाने के बाद जो राहत मिलनी चाहिए थी, वह फिलहाल फाइलों, नोटिसों और चर्चाओं में उलझती नजर आ रही है। और जैसे-जैसे चर्चाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे सियासी गलियारों में कान खड़े और भौंहें टेढ़ी हो रही हैं। कल तक जिन बैठकों में तालियां गूंजती थीं, आज उन्हीं कमरों में फुसफुसाहट है। समर्थक कह रहे हैं "कुछ नहीं होगा", विपक्ष मुस्कुरा रहा है "सब कुछ होगा।" राजनीति की यही खासियत है, यहां भरोसे भी सशर्त और आश्वासन भी अस्थायी होते हैं। जांच एजेंसियों का नाम आते ही बयान बदल जाते हैं कल "षड्यंत्र" था, आज "कानून अपना काम करेगा" हो गया है। सत्ता में रहते हुए हर सवाल "विकास" के फ्रेम में फिट हो जाता है, लेकिन सत्ता से बाहर आते ही वही सवाल "जांच" की फाइल बन जाते हैं। भूपेश बघेल के इर्द-गिर्द भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। मीडिया स्टूडियो में पैनलिस्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे कुंडली हाथ लग गई हो। सोशल मीडिया पर ट्रायल शुरू हो चुका है फैसला पहले, सबूत बाद में। और राजनीति के जानकार जानते हैं कि मुश्किलें सिर्फ आरोपों से नहीं बढ़तीं, बल्कि "संभावनाओं" से बढ़ती हैं।

कर्तव्य पथ पर युवा भारतः संकल्प से सिद्धि का नया अध्याय

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

गणतंत्र का गौरव

26 जनवरी केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं है। यह आत्म-मंथन का अवसर है, यह सोचने का कि एक नागरिक के रूप में हम अपने अधिकारों के प्रति जितने सजग हैं, क्या अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही उत्तरदायी हैं। इसी दिन भारत ने स्वयं को एक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। हमारे संविधान ने हमें केवल गणतंत्र नहीं दिया, बल्कि एक सशक्त, समावेशी और उत्तरदायी राष्ट्र के निर्माण की साझा जिम्मेदारी भी सौंपी। आज जब भारत एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह जिम्मेदारी सबसे अधिक युवाओं के कंधों पर आ टिकती है। देश का वर्तमान भले ही अनुभव और परंपरा से संचालित हो, लेकिन उसका भविष्य युवाओं की सोच, उनके आचरण और उनके मूल्यों से ही आकार लेगा। गणतंत्र की मजबूती का असली पैमाना यही है कि उसका युवा वर्ग अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से स्वीकार करता है।

कर्तव्य की पाठशालाः समाज की सामूहिक जिम्मेदारी

कर्तव्यों की समझ केवल पाठ्यपुस्तकों से नहीं आती। इसके लिए परिवार, समाज और संस्थाओं की साझा भूमिका आवश्यक है। युवाओं को यह बोध कराना होगा कि राष्ट्रप्रेम केवल नारों, प्रतीकों या सोशल मीडिया की अभिव्यक्तियों तक सीमित नहीं है। वह हमारे दैनिक आचरण में दिखाई देता है, अनुशासन में, ईमानदारी में और सामाजिक संवेदनशीलता में। जब कोई युवा यातायात नियमों का पालन करता है, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रखता है, पर्यावरण के प्रति सजग रहता है या समाज के वंचित वर्ग के लिए आगे आता है, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणतंत्र की नींव को मजबूत करता है। यही छोटे-छोटे आचरण लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से जीवंत बनाते हैं।

अधिकार, कर्तव्य और रोजगारः परस्पर पूरक संबंध

समकालीन भारत में युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न रोजगार का है। इस संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। वास्तव में, कर्तव्य और रोजगार परस्पर पूरक हैं। यदि युवा शिक्षा, कौशल विकास और आत्म-अनुशासन को अपना प्राथमिक कर्तव्य मान लें, तो वे केवल रोजगार की प्रतीक्षा करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि नए अवसर सृजित करने वाले बन सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक ही एक कुशल पेशेवर बनता है। जब कोई युवा अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करता है- चाहे वह छात्र हो, कर्मचारी हो, उद्यमी हो या किसान—तो वही उसका राष्ट्र के प्रति सबसे सार्थक योगदान होता है। राष्ट्र निर्माण केवल नीतियों या घोषणाओं से नहीं, बल्कि कार्यस्थलों पर निभाई गई जिम्मेदारियों से होता है।

डिजिटल युग और चुनौती

आज का युग सूचनाओं की तीव्रता का युग है। डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही भ्रम की चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। सोशल मीडिया पर क्षणिक लोकप्रियता और बिना जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति कई बार युवा ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, किंतु यह स्वतंत्रता उत्तरदायित्व से अलग नहीं है। युवाओं को यह समझना होगा कि उनके अधिकार वहीं समाप्त होते हैं, जहाँ से दूसरों के अधिकार प्रभावित होने लगते हैं। असहमति लोकतंत्र की ताकत हो सकती है, पर अराजकता उसकी जड़ों को कमजोर करती है। आज आवश्यकता ऐसे युवाओं की है, जो डिजिटल मंचों पर प्रतिक्रिया देने से पहले संवैधानिक मर्यादाओं और सामाजिक प्रभावों पर विचार करें।

राष्ट्र निर्माणः हर युवा की भूमिका

राष्ट्र निर्माण केवल राजनीति या शासन की परिधि तक सीमित नहीं है। एक शिक्षक जो ईमानदारी से पढ़ाता है, एक डॉक्टर जो सेवा को सर्वोपरि रखता है, एक किसान जो कठिन परिस्थितियों में भी उत्पादन करता है, या एक युवा जो नवाचार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करता है वे सभी राष्ट्र निर्माता हैं। यदि युवा यह संकल्प ले कि वह शॉर्टकट, असहिष्णुता और गैर-जिम्मेदार आचरण से दूरी बनाएगा, तो वही संकल्प भारत के भविष्य की सबसे ठोस आधारशिला बनेगा। इस गणतंत्र दिवस पर आवश्यक है कि हम अधिकारों के उत्सव के साथ-साथ कर्तव्यों के निर्वहन को भी अपना गौरव बनाएं। जब युवा अपने व्यक्तिगत सपनों को राष्ट्र के दीर्घकालिक संकल्पों से जोड़ देगा, तब भारत के विकास पथ को कोई बाधा नहीं रोक पाएगी। एक सशक्त गणतंत्र वही है, जहाँ युवा केवल प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि समाधान की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। जय हिंद

क्या गौ मांस के पैसों से अपनी राजनीति चमका रही हैं भोपाल महापौर मालती राय और उनके राजनीतिक आका?

(पेज 1 का शेष)

इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यदि आरोप सही हैं, तो यह न केवल कानून की अनदेखी है, बल्कि निगरानी तंत्र की विफलता भी दर्शाता है। वहीं, यह भी आवश्यक है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच पूरी हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके और निर्दोष को अनावश्यक रूप से कटघरे में न खड़ा किया जाए। इस प्रकरण ने एक बार फिर यह रेखांकित किया है कि आस्था से जुड़े मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जनता की अपेक्षा है कि सरकार भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून के अनुसार कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में विश्वास बना रहे। वैसे उत्तराखंड में गाय को मिथुन भी कहा जाता है।

स्लॉटर हाउस संचालक पर उठे सवाल

आधुनिक स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें प्रभावशाली संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते नियमों की अनदेखी संभव हो सकी। हालांकि संबंधित पक्षों की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है और कहा गया है कि बिना जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा।

महापौर की भूमिका पर बहस

भोपाल की महापौर मालती राय द्वारा स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर लिए गए निर्णयों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोपों में कहा जा रहा है कि नगर निगम परिषद की औपचारिक स्वीकृति के बिना संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सवालों के घेरे में मंत्री, जवाबदेही से दूरी क्यों?

मध्यप्रदेश की राजनीति में मंत्री विश्वास सारंग का नाम एक बार फिर विपक्ष के तीखे निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में चल रहे कथित अनियमित तंत्र पर मंत्री की चुप्पी संदेह को और गहरा करती है। जब प्रदेश में आस्था, कानून और प्रशासन से जुड़े संवेदनशील मामले सामने आते हैं, तब जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से सबसे पहले स्पष्टता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, न कि बचाव की राजनीति। विपक्ष का कहना है कि जिन मामलों में नैतिकता और कानून की सीधी परीक्षा होती है, वहां मंत्री का रुख अस्पष्ट रहा है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच की गति और दिशा प्रभावित हो रही है। यदि सब कुछ नियमों के तहत है, तो स्वतंत्र और समयबद्ध जांच से डर कैसा?

सारंग का नाम यासीन मछली के संरक्षक होने पर उठा था

इस विवाद के साथ-साथ यासीन मछली से जुड़े ड्रग्स प्रकरण का भी जिक्र फिर से होने लगा है, जिसमें पहले भी मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि उस समय भी कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया था। अब एक बार फिर पुराने मामलों को जोड़कर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के सामने बड़ा सवाल

इन तमाम आरोपों और दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने खड़ा है। क्या वे इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के आदेश देंगे या फिर राजनीतिक सहयोगियों पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए क्लीनचिट दी जाएगी? जनता और संगठन दोनों की निगाहें अब मुख्यमंत्री के अगले कदम पर टिकी हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गांव-गांव तक पहुंची प्रगति की राह, पीएमजीएसवाई से बदला विकास का भूगोल

(पेज 1 का शेष)

पहाड़ी रास्तों से पक्की सड़क तक परिवर्तन की प्रेरक कहानी

जिले की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, दुरूह घाटियों और वनाच्छादित इलाकों में बसे गांव वर्षों तक अलगाव का दंश झेलते रहे। कई गांवों तक पहुंचने के लिए पगडंडियों, नदी-नालों और जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों का सहारा लेना पड़ता था। बरसात के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते थे। ऐसे समय में न तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाना आसान होता था और न ही बच्चों का स्कूल जाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जब इन इलाकों में सड़कों का सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो ग्रामीणों के मन में वर्षों बाद उम्मीद की एक नई किरण जगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रशासन ने कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी। आज वही गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। अब एम्बुलेंस, कृषि वाहन, स्कूल बसें और छोटे-बड़े वाहन बिना बाधा गांवों तक पहुंच रहे हैं। बरसात के दिनों में भी आवागमन बाधित नहीं होता। यह बदलाव केवल दूरी कम होने का नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार का प्रतीक है।

किसानों की बढ़ी आर्थिक रफ्तार, बाजार हुआ पास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की प्राथमिकताओं में किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना प्रमुख रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़कों ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई है। पहले किसान अपनी उपज को बैलगाड़ी या सिर पर ढोकर मंडी तक ले जाते थे। कई बार फसल समय पर बाजार नहीं पहुंच पाती थी और खराब हो जाती थी। आज पक्की सड़कों के कारण ट्रैक्टर, पिकअप और मिनी ट्रक सीधे गांव तक पहुंच रहे हैं। धान, मक्का, कोदो-कुटकी, सब्जियां और लघु वनोपज अब आसानी से मंडियों तक पहुंच रही हैं। परिवहन लागत कम हुई है, समय की बचत हो रही है और खरीदी समय पर होने से किसानों की आय में स्थायी वृद्धि हुई है। ग्रामीण गर्व से कहते हैं कि "सड़क आई तो बाजार हमारे गांव आ गया।" यह बदलाव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की किसान हितैषी सोच को जमीन पर उतारने का जीवंत उदाहरण है।

स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक सुधार

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी चुनौती रही है समय पर इलाज। पहले बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में घंटों लग जाते थे। कई बार एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाती थी। सड़क निर्माण के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब 108 एम्बुलेंस गांवों तक सीधे पहुंच रही है। गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित हो रहा है। टीकाकरण, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। गंभीर मरीजों को समय पर जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मंशा पीएमजीएसवाई की सड़कों के माध्यम से साकार हो रही है।

शिक्षा के खुले नए द्वार, ड्रॉपआउट में कमी

शिक्षा के क्षेत्र में भी सड़कों ने क्रांतिकारी बदलाव किया है। पहले दूरस्थ गांवों के बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते थे। कई बच्चे खतरनाक रास्तों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। अब स्कूल वैन, बसें और ऑटो आसानी से गांवों तक पहुंचते हैं। शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच पा रहे हैं। छात्र उच्च शिक्षा के लिए कस्बों और शहरों तक आसानी से आ-जा रहे हैं। इसका सीधा असर ड्रॉपआउट दर में कमी के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली नीति को सड़क कनेक्टिविटी ने मजबूती दी है।

रोजगार, व्यापार और पर्यटन को मिला नया बल

पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण से हजारों ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सड़कों के साथ ही स्थानीय व्यवसाय फले-फूले हैं। गांवों में किराना दुकानें, ढाबे, गैराज और परिवहन सेवाएं शुरू हुई हैं। निर्माण सामग्री की सप्लाई से लेकर रखरखाव तक स्थानीय लोगों को लाभ मिला है। साथ ही, एमसीबी जिले के प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। स्थानीय गाइड, होम-स्टे और छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं। यह सब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उस सोच का परिणाम है, जिसमें विकास को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का साधन माना गया है।

प्रशासन की सक्रियता, गुणवत्ता और गति पर जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। रोड बेस, साइड ड्रेनेज, पुल-पुलियों, सुरक्षा संकेतक और रिफ्लेक्टर जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे पीएमजीएसवाई की सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहें।

भविष्य की ओर मजबूत कदम

एडिशनल पैकेजों के तहत जिले में कई नए मार्ग स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण प्रगति पर है। लक्ष्य स्पष्ट है एमसीबी जिले का कोई भी गांव सड़क विहीन न रहे। आपदा या बरसात के समय भी आवागमन बाधित न हो और सभी शासकीय सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पीएमजीएसवाई ने एमसीबी जिले में सड़कों को केवल रास्ता नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और परिवर्तन की पहचान बना दिया है। आज यह जिला इस बात का सशक्त उदाहरण है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो और नीयत स्पष्ट हो, तो विकास पहाड़ों और जंगलों को पार कर गांव-गांव तक पहुंचता है।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही महिला पत्रकार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गुजरात के अध्ययन भ्रमण से लौटे महिला पत्रकारों के दल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिला पत्रकार अपने साहस से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही हैं। महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि विगत वर्ष महिला दिवस पर उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष महिला पत्रकारों को भी अध्ययन भ्रमण पर भेजे जाने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्हें बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री ने उन सभी की इस इच्छा को पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं से चर्चा के दौरान कहा कि इस अध्ययन भ्रमण के दौरान आप सभी ने गुजरात विधानसभा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, राजकोट, पोरबंदर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझा है। आने वाले समय में ये अनुभव आपकी कलम को और भी समृद्ध करेगा, जिसका लाभ पत्रकारिता जगत के साथ ही आपके पाठकों भी मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का यह तीसरा वर्ष है। इस वर्ष को हम महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महिला पत्रकारों से उनके अध्ययन भ्रमण के अनुभवों को

मुख्यमंत्री ने गुजरात के अध्ययन भ्रमण से लौटे महिला पत्रकारों के दल से की मुलाकात

किताब के रूप संजोने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह ना सिर्फ आपके लिए इस भ्रमण को हमेशा के लिए यादगार बनाएगा बल्कि अन्य लोग भी आपकी किताब को पढ़कर गुजरात के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात एक समृद्ध और मॉडल राज्य है। गुजरात की एक खासियत यह भी है कि वहां सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। अमूल सहकारिता का एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें मुख्यतः महिलाएं शामिल है। छत्तीसगढ़ में भी हम सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम सभी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। मंत्रालय में अब ई-फाइल प्रणाली लागू है। मुख्यमंत्री साय ने महिला पत्रकारों से अपनी गुजरात यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि गुजरात का सीएम डैशबोर्ड देश का सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से एक जगह बैठकर ही पूरे प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास की नींव रखी थी, हम गुजरात जैसी व्यवस्थाओं को यहां भी लागू कर रहे हैं। महिला पत्रकारों ने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों का भी आभार जताया जिन्होंने आठ दिवसीय इस अध्ययन भ्रमण में उनका पूरा ख्याल रखा। इस अवसर पर आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल, अपर संचालक जनसंपर्क संजीव तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह सहित जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण और महिला पत्रकार उपस्थित थे।

जगत प्रवाह

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
लोक निर्माण विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
निर्माण उच्च गुणवत्ता का आधार

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
खनिज विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
प्रकृति हमारे जीवन का आधार

मान.प्रहलाद सिंह पटेल
केबिनेट मंत्री म.प्र.शासन
26 जनवरी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
जल संसाधन
नर्मदापुरम (म.प्र.)
जल ही जीवन है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
आबकारी विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
मिलावट से बचें

आन देश की शान देश की इस देश की हम संतान हैं,
तीन रंगो से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है।
26
गणतंत्र दिवस
सौजन्य से:- समस्त पार्षदगण एवं समस्त स्टाप नगरपालिका परिषद देवरी।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
भारत पेपर इण्डस्ट्रीज
नर्मदापुरम (म.प्र.)
जीवन में शिक्षा अनमोल है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
रेशम उद्योग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
धागा हर कड़ी जोड़ता है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
नर्मदापुरम (म.प्र.)
यातायात के नियमों का पालन करें
कृपया हेलमेट का प्रयोग करें

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
जिला अस्पताल
नर्मदापुरम (म.प्र.)
स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
नगर पालिका परिषद
नर्मदापुरम (म.प्र.)
समस्त करो का भुगतान समयावधि में करें

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
जनपद परिषद
नर्मदापुरम (म.प्र.)
गांव हमारी धरोहर

नोबल परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को
26 January
नोबल परिवार की शैक्षणिक संस्थाएं
- नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सागर
- नोबल कॉलेज, सागर (डिग्री कॉलेज)
- नोबल डिस्टेंस लर्निंग सेंटर (चित्रकूट, माखनलाल, भोज वि.वि.)
- नोबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर(NSDC), सागर
- नोबल पब्लिक स्कूल, देवरी (Affiliated to CBSE)
- NIOS स्टडी सेंटर, देवरी
- नोबल कॉलेज, देवरी
- नोबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर(NSDC), देवरी
- नोबल पब्लिकेशन

गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें...
वन विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
पेड़ लगाएं जीवन बचाएं

समस्त देशवासियों को आजादी के महापर्व
26 जनवरी
समस्त देशवासियों को
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
की सभी देशवासियों
को हार्दिक शुभकामनाएं।
हर्ष यादव महासचिव,म.प्र.कांग्रेस कमेटी,पूर्व केबिनेट मंत्री
एवं विजय श्री गैस एजेंसी देवरी।

नमामि देवी नर्मदे

समस्त नगरवासियों को नर्मदा जयंती एवं
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं।

आभार अभिनंदन

देवरी नगरपालिका अध्यक्ष निर्वाचन में मिले अभूतपूर्व समर्थन और आशीर्वाद के लिए देवरी नगर परिवार की देवतुल्य नागरिकों- मातृशक्तियों का सादर वंदन..कोटि कोटि आभार,

नगर के विकास के संघर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारथी बने
सहभागी, सहयोगियों एवं मार्गदर्शक जागरूक जनों का

आभार..वंदन.. अभिनंदन

नेहा अलकेश जैन अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवरी

गणतंत्र का हरा संकल्प : पर्यावरण रक्षा हमारा कर्तव्य

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

26 जनवरी हमारे देश के लिए गौरवशाली ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने आजादी के लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद इसी दिन हमारी संसद में भारतीय संविधान को पास किया था। खुद को संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के साथ ही भारत के लोगों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत का गणतंत्र दिवस न केवल संविधान की पवित्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर भी है जब हम अपने पर्यावरण के प्रति कर्तव्य को नया आयाम दे सकते हैं। कर्त्तव्यपालन के प्रति सतत जागरुकता से ही हम अपने अधिकारों का निरापद रखने वाले गणतंत्र का पर्व सार्थक रूप से मना सकेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन यह अधिकार तब तक अधूरा है जब तक देश के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियां को ख़त्म नहीं कर देते हैं। बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पृथ्वी पर संकट मंडराने लगा है।

आमतौर हम सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन खुद से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम देश के पर्यावरण के लिए कुछ नही करते और केवल सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे लिए करे। हमारा संविधान अनुच्छेद 48 ए और 51 क (ग) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य बनाता है, जो हमें वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा का दायित्व सौंपता है। इस हरे संकल्प को अपनाते हुए गणतंत्र दिवस पर हर नागरिक पेड़ लगाने का प्रण ले सकता है, क्योंकि एक छोटा-सा पौधा ही धरती को हरा-भरा बनाए रखने का प्रतीक बन जाता है। प्लास्टिक का त्याग कर जूट या कपड़े के थैलों का उपयोग, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन और ऊर्जा बचत के उपाय अपनाना हमारी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बन जाए। स्वच्छता अभियान को गति देकर गीला-सूखा कचरा अलग-अलग करना और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में योगदान देना राष्ट्र निर्माण का सच्चा स्वरूप है। गणतंत्र की आत्मा में पर्यावरण रक्षा का समावेश हमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास जैसी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम नदियों को स्वच्छ रखने, वनों की कटाई रोकने और जैविक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं, तो हम न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और जल का उपहार भी देते हैं। यह हरा संकल्प गणतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे शक्तिशाली कदम है, जो व्यक्तिगत प्रयासों से सामूहिक क्रांति लाता है। गणतंत्र की सार्थकता तभी होगी जब हरेक व्यक्ति को काम, भोजन एवं स्वच्छ पर्यावरण मिले।

धामी सरकार की 'जनता के द्वार' मुहिम लोग हो रहे लाभांवित

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' पहल आम लोगों के लिए काफी प्रभावी साबित हो रही है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक प्रदेश भर में 452 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 3,56,992 से अधिक लोगों ने सीधे तौर पर लाभ उठाया है। सरकार का लक्ष्य इस मुहिम के जरिए शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करना है। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल आयोजित 7 कैंपों में 2,933 लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान पाया। यह पहल शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन कैंपों की खासियत यह है कि यहां आम नागरिकों को कई सरकारी विभागों से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। लोगों को राजस्व, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेंशन और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। शिकायतों का निस्तारण भी इन्हीं कैंपों में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

सुशासन मॉडल का सफल क्रियान्वयनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम इसी सोच को जमीन पर उतारने का एक प्रयास है। इस पहल से न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि आम जनता का सरकार और शासन प्रणाली पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। प्रदेश भर से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को मुख्यमंत्री धामी के जन-केंद्रित और जवाबदेह शासन मॉडल की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।

भगवान बनकर आई टिमरनी पुलिस, पति-पत्नी की जान बचाने पर लोगों ने की तारीफ, टिमरनी पुलिस की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। जनपद पंचायत टिमरनी के सामने स्थित अंडर ब्रिज के पास शराब के नशे में एक पति पत्नी रेल्वे टैंक पर जाकर जान देने का कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही टिमरनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सूझबूझ से दोनों को सुरक्षित रेल्वे टैंक से हटाकर उनकी जान बचाई। इस दौरान टिमरनी थाना प्रभारी मुकेश गौड़ रामविलास करपे, अभिलेश चतुर्वेदी सहित पुलिस स्टाफ मौक़े पर मौजूद रहा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित शासकीय अस्पताल टिमरनी पहुंचाया। जहां उनका उपचार जारी है। थाना प्रभारी मुकेश गौड़ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही टीम के साथ तुरंत मौके पर रवाना हुए। समय रहते कार्यवाही कर दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। वर्तमान में उनकी हालत स्थिर है और आगे आवश्यक कानूनी व परामर्शात्मक कार्यवाही की जा रही है। टिमरनी पुलिस की इस मानवीय और संवेदनशील कार्यवाही से एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय नागरिकों ने टिमरनी पुलिस की तत्परता व मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की है।

स्वाभिमान, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रतीक है कमलनाथ का 15 माह का कार्यकाल

(पेज 1 का शेष)

कमलनाथ की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक विवेकशीलता रही है। मध्यप्रदेश की राजनीति में अक्सर सत्ता परिवर्तन और दल-बदल जैसी घटनाएँ देखने को मिलती रही हैं। ऐसे माहौल में कई नेता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने राजनीतिक कदम उठाते हैं, लेकिन कमलनाथ ने हमेशा पार्टी लाइन और अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह साबित किया कि यदि कोई नेता अपने स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों से समझौता करता है, तो वह सिर्फ अस्थायी लाभ पा सकता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टिकोण और सम्मान खो देता है।

कमलनाथ की दीर्घकालिक सोच को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व की सबसे बड़ी मिसाल उनके 15 महीने के कार्यकाल का वह समय है, जब उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत लालच के राजनीतिक परिस्थितियों का सामना किया। उनके शासनकाल में अफसरशाही और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया गया। कमलनाथ ने अपने अफसरों और मंत्रियों के साथ मिलकर ऐसे रणनीतिक उपाय तैयार किए, जो प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार में सहायक थे। यह रणनीति इतनी सुदृढ़ और दूरगामी थी कि आज भी मुख्यमंत्री उनकी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कमलनाथ केवल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके विचार और नीति भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक हैं।

मध्यप्रदेश के लिए अहम है राज्यसभा सीट

जून 2026 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें रिक्त हो रही हैं। राज्य में राज्यसभा के तीन सदस्यों के पद रिक्त हो रहे हैं। प्रदेश से कांग्रेस को एक सीट मिलना तय है। ऐसे में मध्यप्रदेश कांग्रेस से प्रत्याशी के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान को चयन में सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि इस समय प्रदेश कांग्रेस बुरे वक्त से गुजर रही है। प्रत्यासी के चयन में हाईकमान को 2028 की रणनीति को भी देखना होगा। बेहतर होगा कि पार्टी किसी अनुभवी और कुशल नेतृत्वकर्ता को इस पद पर आसीन कराये।

चाणक्य नीति और कमलनाथ सरकार का पतन

मध्यप्रदेश की राजनीति में 2018-19 के दौर में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने केवल 15 महीने ही शासन किया। इसका एक प्रमुख कारण था कांग्रेस के भीतर की गुप्त राजनीतिक रणनीतियां, जिन्हें पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को चाणक्य नीति के रूप में देखा जाता है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, कमलनाथ के खिलाफ कई पूर्व मंत्री और विधायक भाजपा से संपर्क में थे। इस समय का लाभ उठाकर कांग्रेस के नेताओं ने गुप्त रूप से दल के भीतर असंतोष और सत्ता संघर्ष को हवा दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कमलनाथ को अपने स्वाभिमान और पार्टी लाइन के बीच कठिन निर्णय लेना पड़े। यह घटना साबित करती है कि राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है यह रणनीति, समझदारी और दूरदर्शिता का खेल भी है। कांग्रेस नेताओं की चाणक्य नीति ने कमलनाथ सरकार के कमजोर पड़ते पक्ष और भीतर के मतभेदों का कुशलतापूर्वक लाभ उठाया।

भाजपा नेताओं में शुरू हुई अंतर्कलह

मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं और विधायकों के बीच वर्तमान में चल रही आंतरिक कलह को देखते हुए यह समझना आवश्यक है कि कमलनाथ की शैली और उनके नेतृत्व की गहराई कितनी प्रशंसनीय थी। जहाँ अन्य नेता केवल व्यक्तिगत लाभ और सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं कमलनाथ ने अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। उनके नेतृत्व में न केवल प्रशासनिक सुधार हुए, बल्कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कमलनाथ के प्रति कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनकी नीति के प्रति विश्वास यह दर्शाता है कि उनके योगदान को केवल तत्कालीन दौर में नहीं बल्कि दीर्घकालीन रूप से भी महत्व दिया जाता है। कमलनाथ का नेतृत्व केवल एक राजनीतिक पद तक सीमित नहीं था यह नेतृत्व विचार, नीति और आदर्श का प्रतीक था। उनके कार्यकाल में किए गए प्रयास और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता आज भी प्रदेश की राजनीति में मार्गदर्शक बनी हुई है।

स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता

कमलनाथ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनका अदम्य स्वाभिमान है। जब राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं थीं और सत्ता की कुर्सी बनाए रखना कठिन हो गया, तब उन्होंने अपने स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देना उचित समझा। यह कदम केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक आदर्श नेतृत्व के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रशंसनीय था। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि एक सच्चा नेता केवल पद के लालच में नहीं बल्कि समाज और पार्टी के हित में निर्णय लेता है। इस निर्णय ने उन्हें मध्यप्रदेश की राजनीति में एक स्थायी और आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। कमलनाथ का एक अन्य पहलू उनकी रणनीतिक कुशलता है। उनके कार्यकाल के दौरान और उसके बाद की परिस्थितियों ने यह दिखाया कि कमलनाथ न केवल तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी सटीक विश्लेषण करते हैं।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कर रहे नेतागिरी, ब्लॉक के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो रही जमकर राजनीति

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 2 ब्लॉक साइखेड़ा और चीचली शामिल हैं। देखने में आ रहा है कि स्कूल शिक्षामंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेलगाम होकर मंत्री की साख पर बट्टा लगाने को आतुर हो रहे हैं। नीति, नियम, निर्देशों को ताक पर रखकर वह जमकर नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया फिर से एक बार सामने आया है जब साईखेड़ा बीईओ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर चीचली विकासखंड मे जाकर बच्चों को कपडे वितरण कार्यक्रम का प्रोपगेंडा रचा। एक शासकीय शिक्षा अधिकारी का ऐसा काम करना क्या उचित है। लोगों के मुताबिक यदि करना था तो चीचली विकासखंड शिक्षा अधिकारी को साथ रखना था या जिला शिक्षा अधिकारी के दल को साथ लेकर जाना चाहिए था। मगर कुछ संदिग्ध कार्यशैली वाले शिक्षकों के साथ लेकर जाते हैं। वन विहार को जाते हैं, दावत करते हैं। आखिर रुपये किस निधि से खर्च किए जा रहे हैं। जो काम राजनीतिक लोगों को करना चाहिए या पार्टी कार्यकर्ता को करना चाहिए वह शासकीय अधिकारी होकर भी शिक्षा अधिकारी साइखेड़ा द्वारा किया जा रहा है। यह सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल है और शासकीय मर्यादा और गरिमा को भंग करने वाला है। अब देखना है कि स्वयं शिक्षा मंत्री या जिला शिक्षा अधिकारी संज्ञान लेकर इस मामले पर कब कोई कड़ा रुख अपनाते हैं।

लकड़ी से भरा पिकअप वाहन जप्त, आरोपियों की तलाश जारी

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। वन परिक्षेत्र गौरझामर के अंतर्गत वन स्टाफ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़राई के जंगल से सागौन लकड़ी का अवैध परिवहन किया गया जाना है। वन स्टाफ द्वारा अपनी सजगता दिखाते हुये संदिग्ध क्षेत्र की तीन तरफ से घेराबंदी कर एक लोडिंग पिकअप वाहन जो कि गढ़ाकोटा से सागौन लकड़ी लेने पडराई के पास जंगल में आया था उसे घेर लिया गया। वाहन में सवार आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। पिकअप वाहन को मय वनोपज के साथ जप्त किया जाकर शासकीय अभिरक्षा में लाया गया एवं वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

मनरेगा का नाम परिवर्तन सुनियोजित षडयंत्र

-रघु ठाकुर

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर वीबी- जीरामजी कर दिया है। संसद में प्रतिपक्ष दलों ने इस नाम बदलने का तीखा विरोध किया और जो होना स्वाभाविक भी था। भाजपा और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल 11 वर्षों से बल्कि अगर इतिहास में जाया जाए तो 1930 के बाद से ही महात्मा गांधी को बदनाम करने, उनका अपमान करने व उनके विरुद्ध अन्य प्रकार के झूठ फैला रही है और अब इन पिछले 11 वर्षों में इसमें ज्यादा गति आई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है। स्व. बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने पर एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी और जिस प्रकार उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में न्यायपालिका ने रिहा करने का आदेश दिया और कार्यवाही पर रोक लगाई, परंतु आज तक देश में महात्मा गांधी के खिलाफ गंदी-गंदी टिप्पणी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कार्रवाई या दंड से विचार नहीं मरते। मैं चाहता हूं कि समाज के लोग आगे आकर ऐसे झूठे आरोपों का प्रतिकार कर सुनियोजित झूठ फैलाने वालों को तार्किक उत्तर देकर निरुत्तर करें। बाल ठाकरे की घटना का उल्लेख तो मैंने यह बताने के लिए किया है कि देश में दो प्रकार के कानून चलते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि संघ-भाजपा के लोग अभी तक ऊपरी तौर पर महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, परंतु उनके ही नीचे के अनुयायी महात्मा गांधी के खिलाफ गंदे शब्दों के प्रयोग करते हैं। ऊपर से नमन और नीचे से कटन की यह संघ की शिक्षा है, इसके बहुत सारे प्रमाण मैं दे सकता हूं, परंतु अभी वह मेरा विषय नहीं है।

भाजपा के नेताओं और सत्ताधीशों के लिए शब्द कितने अर्थहीन हैं और केवल शब्दों तक सीमित हैं इसका प्रमाण उस दिन मिला जब संसद में उत्तर देते हुए कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में हैं। यह कितना विचित्र था कि जिनके दिलों में महात्मा गांधी हैं उनके कागजों से महात्मा गांधी हटाए जा रहे हैं। यह दिल, दिमाग और शब्दों की कागजों से दूरी शोध का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने के पीछे संघ के तीन उद्देश्य हैं-

1. एक वे देखना और तोलना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाने पर देश में क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उनका अगला चरण नोटों पर से भी गांधी का चित्र हटाने का हो सकता है। उन्हें अंतरमन से गांधी से इतनी घृणा है कि वह गांधी की हर याद को मिटाना चाहते हैं। यह प्रयोग उन्होंने सरकार बनने के बाद तब भी किया था जब केंद्र सरकार ने सफाई का अभियान चलाया था और जिन महात्मा गांधी ने 19वीं सदी के आरंभ से ही जब न संघ का जन्म भी नहीं हुआ था, न मोदी का, तब सफाई का अभियान और संदेश दुनिया को दिया था। तब भी उसमें बापू का चित्र कहीं नजर नहीं आया केवल चश्मा रखा गया, ताकि कोई आरोप लगे तो कहा जाए कि हमने बापू का चश्मा लिया है।

2. दरअसल सरकार को मनरेगा के जो मूल प्रावधान थे उनमें ही परिवर्तन करना था क्योंकि मनरेगा जैसी योजना उनकी नीति के अनुकूल नहीं है। 2014 से 19 के बीच उन्होंने मनरेगा का बजट कम किया था, यहां तक कि काफी समय तक काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तक नहीं चुकी थी, फिर कई महीनों के बाद लाचार होकर लंबित राशि का एक हिस्सा जारी किया गया। हालांकि वह भी आवश्यकता के अनुसार और लंबित भुगतान के अनुसार पर्याप्त नहीं था। दरअसल मोदी सरकार इस योजना से मुक्ति चाहती है। इस योजना में जो संशोधित प्रावधान किए गए हैं वह बहुत ही चलाकी भरे और अप्रत्यक्ष रूप से कानून को अप्रभावी बनाने वाले हैं। जैसे यह कहा गया है कि सरकार ने कार्य दिवस बढ़कर वर्ष में 100 दिन से 125 दिन कर दिए हैं, परंतु इसके साथ यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि यह रोजगार उपलब्ध बजट के अनुसार ही दिए जाएंगे, यानी पहले मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन काम देने की सरकार को बाध्यता थी अब सीमा तो 125 दिन की गई है, परंतु बाध्यता नहीं है। जितना पैसा होगा उतने ही दिन काम दिया जाएगा और इसका अर्थ हुआ कि जब बजट नहीं मिलेगा तो काम नहीं मिलेगा। तथा अपने आप बाध्यता की बजाय योजना सरकार के मन पर निर्भर करेगी।

3. सरकार ने नाम बदलने और महात्मा गांधी के नाम की बजाय वीबी राम जी नाम करने के पीछे यह भी रणनीति दिखती है कि प्रतिपक्ष महात्मा गांधी के नाम को लेकर हल्ला गुल्ला करेगा, बहस करेगा, विरोध करेगा और हुआ भी तो भी उन प्रावधानों पर कोई चर्चा नहीं हो सकेगी, जो मनरेगा की मूल आत्मा और विचार को समाप्त करने वाले हैं तथा मौका पाकर भाजपा यह भी प्रचारित करेगी कि हमने तो राम का नाम जोड़ा है, प्रतिपक्ष राम को नहीं मानता इसलिए विरोध कर रहा है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष जाने अनजाने में भाजपा नेतृत्व के षड्यंत्र का शिकार हो गया।

अच्छा होता कि पहले उन प्रावधानों पर संसद में बहस होती जिनके माध्यम से मनरेगा कानून को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, देश की जनता इन तथ्यों को जान सकती। कृषि मंत्री शिवराज ने संसद में उत्तर देते हुए कहा कि हमने श्रमिकों को मजदूरी के लिये देने की राशि डेढ़ लाख करोड़ रुपये कर दी है, परंतु किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि बजट तो मार्च में आना है उसके पहले आपने वृद्धि कैसे कर दी? तथ्य तो यह है कि लगभग 30000 करोड़ रुपए औजार आदि की खरीद और श्रमिकों की मजदूरी का पिछला बकाया है, जो अभी तक नहीं दिया गया। मैं मान लेता हूं कि मनरेगा के जो उद्देश्य थे उनमें कई कमियां सामने आई हैं, जैसे श्रमिकों को रोजगार के नाम पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों गांव के ताकतवर लोगों और कर्मचारियों ने मिलकर भारी भ्रष्टाचार किया है। बगैर काम के ही जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और दबंगों के गठजोड़ ने पैसा निकाल लिया है, परंतु यह दोष तो व्यवस्था का या तंत्र का है न कि कानून का। दूसरे चूंकि ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के लिए काम करने को मजदूर नही मिलते इसलिए अधिकारियों को मशीनों से कराना पड़ता है जो कि कानून के भावना और उद्देश्य के खिलाफ है।

राजवीरों की बात

नितिन नबीन : संगठन से शासन तक की सशक्त राजनीतिक यात्रा

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता नितिन नवीन बिहार की राजनीति में एक सक्रिय, कर्मठ और जनसंवेदनशील नेतृत्व के रूप में पहचाने जाते हैं। वे लंबे समय से संगठनात्मक कार्य, विधायी दायित्व और जनसेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे हैं। सरल व्यक्तित्व, स्पष्ट विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण उनकी राजनीतिक पहचान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नितिन नवीन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उनका पालन-पोषण एक संस्कारयुक्त एवं सामाजिक रूप से जागरूक परिवार में हुआ, जहाँ राष्ट्रवाद, अनुशासन और सेवा के मूल्य बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा पटना में ही पूर्ण की। छात्र जीवन के दौरान ही उनका झुकाव राष्ट्रवादी विचारधारा और सामाजिक गतिविधियों की ओर हो गया था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने विद्यार्थी परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर की। संघ की विचारधारा, अनुशासन और सेवा-भाव ने उनके व्यक्तित्व को दिशा दी। संगठनात्मक कार्य करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर समाज की समस्याओं को समझा और समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की मजबूत नींव बना। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। उनकी कार्यशैली में संगठन के प्रति निष्ठा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और आम जनता से सीधा जुड़ाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे कार्यकर्ताओं के बीच सहज उपलब्ध रहने वाले नेता माने जाते हैं, जिससे पार्टी संगठन को निरंतर मजबूती मिली है।

नितिन नवीन पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी। सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। उनके कार्यकाल में क्षेत्र में कई बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। विधानसभा में नितिन नवीन ने सदैव जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वे एक सशक्त वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। उनकी छवि एक अनुशासित, मर्यादित और सक्रिय विधायक की रही है, जो सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाकर कार्य करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र में भी नितिन नवीन की सक्रिय भूमिका रही है। वे युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में निरंतर सहभागिता करते रहे हैं। आपदा अथवा संकट की परिस्थितियों में भी वे आम जनता के बीच रहकर सहायता कार्यों में सक्रिय दिखाई देते हैं। वैचारिक रूप से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यों और विकासोन्मुख राजनीति के समर्थक हैं। वे मानते हैं कि मजबूत संगठन, सशक्त नेतृत्व और जनभागीदारी के माध्यम से ही समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण संभव है। नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा संगठन की तपस्या, जनसेवा की प्रतिबद्धता और विचारधारात्मक स्पष्टता का उदाहरण है। बिहार की राजनीति में वे एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हैं, जो अनुभव, ऊर्जा और संगठनात्मक क्षमता के साथ भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं।

मोदी संग बढ़त है छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

पीएम आवास योजना

26 लाख से अधिक परिवारों को पक्की छत देने वाले

महतारी वंदन योजना

70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले

पीएम किसान सम्मान निधि

26 लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाले

तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹5500 मानक बोरा

13 लाख संग्राहक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले

उद्यम क्रांति योजना

युवाओं को स्वरोज़गार के लिये **50% सब्सिडी** पर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाले

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने वाले

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

37 लाख महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाले

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना

37 हजार से अधिक राम भक्तों को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराने वाले

छत्तीसगढ़ में शांति, विश्वास और विकास का मार्ग हो रहा प्रशस्त

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. : 13643/ 1

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)